IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

भागलपुर जिला के सरकारी और गैर–सरकारी स्कूलों के छात्रों के बीच सीखने की गुणवत्ता का एक तुलनात्मक अध्ययन

अजय कुमार

शोध छात्र, स्नातकोत्तर मनोविज्ञान विभाग, तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर

सारः गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एक गतिशील अवधारणा है क्योंकि यह समय के साथ विकसित होती है और यह सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण, सीखने के माहौल और सीखने के परिणामों के अधीन है। ये सीखने के परिणाम छात्रों की सीखने की गुणवत्ता से संबंधित हैं क्योंकि गुणवत्तापूर्ण सीखने की सबसे अधिक संभावना तब होती है जब छात्र सक्रिय रूप से और उद्देश्यपूर्ण ढंग से उन गतिविधियों और मुद्दों से जुड़े होते हैं जिन्हें वे महत्वपूर्ण मानते हैं। वर्तमान अध्ययन का उद्देश्य गैर–सरकारी और सरकारी स्कूल के छात्रों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की तुलना करना था। वर्तमान समस्या का अध्ययन करने के लिए वर्णनात्मक सर्वेक्षण पद्धति का प्रयोग किया गया और इसमें 100 स्कूली छात्रों ने भाग लिया। आंकड़ा एकत्र करने के लिए स्वनिर्मित प्रश्नावली का उपयोग किया गया। निष्कर्ष से पता चला कि सरकारी स्कूलों की तुलना में गैर–सरकारी स्कूल में सीखने की गुणवत्ता बेहतर पाई गई और सरकारी स्कूल की छात्राओं की सीखने की गुणवत्ता बेहतर पाई गई।

मुख्य शब्दः सरकारी विद्यालय, गैर–सरकारी विद्यालय, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लिंग, भागलपुर।

परिचय

शिक्षा वह सबसे प्रभावी उपकरण है जो व्यक्ति की धारणा को बदल देता है। प्राचीन काल से ही इसे मनुष्य की तीसरी आंख माना गया है जो उसे सभी सांसारिक मामलों को देखने की अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। लोगों ने अपना आधा जीवन विभिन्न शिक्षण संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करने में व्यतीत कर देता है ताकि उसका भविष्य अच्छा और सुखमय हो सके। लेकिन उनमें से केवल कुछ ही बेहतर शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं। इसका कारण अप्रभावी शिक्षा नीतियां, शिक्षण रणनीतियां और शिक्षण सामग्री है। हाल के दिनों में, शिक्षा में सहायता करने वाली नीति धीरे–धीरे स्कूली शिक्षा के दृष्टिकोण से सीखने की गुणवत्ता में सुधार करने की ओर स्थानांतरित हो गई है। उम्मीद की जा रही है कि यह बदलाव भविष्य में शिक्षा में विकास के लिए वैश्विक विकास ढांचे का नेतृत्व करेगा। शिक्षा की गुणवत्ता आर्थिक विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। हनुशेक और किम्को (2000) और बैरो (2001) ने पाया कि परीक्षण स्कोर स्कूली शिक्षा की वर्षों की उपलब्धि की तुलना में वास्तविक व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का बेहतर व्याख्याकार हैं।

यह देखा गया है कि भारत में छात्रों की गुणवत्ता का स्तर बहुत ही निम्न है, साथ ही शिक्षकों की योग्यता और उपस्थिति भी समान रूप से समस्याग्रस्त है, सरकारी स्कूलों में 75% से कम प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक हैं। इसके साथ ही खराब बुनियादी ढांचा, भीड़भाड़ वाले कमरे, शिक्षण सामग्री और अध्ययन कौशल तकनीकों की कमी भी अच्छे शिक्षण वातावरण के लिए बाधाएं हैं। ऐसे बहुत से शोध अध्ययन हुए हैं जो इस दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं कि उपरोक्त संपूर्ण कारक सीधे स्कूली छात्रों की सीखने की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। हेन्स (1993) के अनुसार अध्ययन कौशल तकनीकें खराब अध्ययन कौशल आदतों वाले छात्रों के लिए शैक्षणिक उपलब्धि को बढ़ाने में भी मदद करती हैं। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अध्ययन कौशल को हाई स्कूल स्तर पर पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि कई हाई स्कूल के छात्रों में पढ़ने, सोचने और अध्ययन कौशल की

कमी है। बहुत से शोधकर्त्ताओं का कहना है कि आधुनिक मल्टीमीडिया और मल्टीमॉडल शिक्षण रणनीतियों का उपयोग स्कूल के छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धि को बढ़ा सकता है।

समस्या का उद्भव एवं औचित्य

आजकल सरकार स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर ध्यान केंद्रित कर रही है तथा शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया में सुधार के लिए विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए हैं। सरकार ने माध्यमिक शिक्षा विभाग में सभी सरकारी स्कूलों के लिए समय–समय पर स्कूल ग्रेडिंग और निगरानी प्रणाली के लिए एक वेब पोर्टल भी पेश किया है, जो माध्यमिक शिक्षा में गुणवत्ता सुधार में मदद करता है। हालाँकि ये ऑनलाइन कार्यक्रम समग्र स्कूल कार्यक्रम पर विभिन्न संस्थानों से फीडबैक प्राप्त करने का एक माध्यम मात्र हैं, लेकिन तथ्य यह है कि कई संस्थान बुनियादी आवश्यकताओं को गंभीरता से नहीं लेते हैं और उन्हें पूरा नहीं करते हैं, वे केवल अपने अधिकारियों के दबाव में जानकारी भरने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा केवल ज्ञान, समझ और संज्ञानात्मक कौशल के क्षेत्र पर सीखने पर केंद्रित नहीं है क्योंकि यह एकतरफा नहीं है। हालाँकि यह अपने छात्रों और कर्मचारियों के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। इसलिए, प्रभावी शिक्षण के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ाया जा सकता है क्योंकि इसमें शारीरिक सौंदर्य, बौद्धिक और व्यक्तिगत आयाम शामिल हैं। लेकिन सीखने में किसी व्यक्ति के विश्वास, स्वभाव, दृष्टिकोण और मूल्य सभी व्यक्तिगत शिक्षण को प्रभावित करते हैं और प्रभावी व्यक्तिगत शिक्षण शिक्षार्थी की खुले दिमाग वाली प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। इसलिए, शोधकर्ता यह जानने में रुचि रखता है कि क्या भागलपुर जिले के सरकारी और गैर–सरकारी स्कूलों के छात्रों में सीखने की गुणवत्ता में अंतर है।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा

शब्द "गुणवत्ता" लैटिन शब्द "क्वालिटास" से लिया गया है जिसका अर्थ है किसी चीज़ की उत्कृष्टता की डिग्री (ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, 2003)। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वह सीख है जो व्यक्ति की ज्ञान और समझ प्राप्त करने की क्षमता को बढ़ावा देती है जिसका उपयोग वास्तविक परिस्थितियों में वैध, सूचित निर्णय लेने के लिए किया जाता है और विचारों, समझ और विचारों को साझा करने में व्यक्ति की सकारात्मक क्षमता को भी बढ़ाता है।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अर्थ केवल तथ्यों के बारे में पढ़ाना नहीं है, बल्कि यह भी सीखना है कि उन तथ्यों को कैसे समझाया या निर्धारित किया जाए जो दूसरों के लिए आसानी से समझ में आ सकें। इसमें बहुत सारी सोच, व्यक्तिगत कार्य क्षमता, दूसरों के साथ संवाद, गहन दायरे वाले विषय शामिल हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का मतलब सिर्फ परीक्षा में उच्च अंक और ग्रेड लेना नहीं है, बल्कि इसका मतलब सामाजिक कौशल सीखना और जीवन की परीक्षा में अच्छा स्थान हासिल करना है। दूसरे तरीके से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सामाजिक कौशल पर काम करना और जीवन की वास्तविकताओं का सामना करने या मानवाधिकारों के बारे में जानने के लिए तैयार करना है।

साहित्य समीक्षा

राणा रूबब और अब्दुल गफूर अवन (2020) के शोध पत्र 'सरकारी और निजी माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता का एक तुलनात्मक अध्ययन' का मुख्य उद्देश्य पाकिस्तान के दो जिलों खानवाल और वायररी में सरकारी और निजी माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता का तुलनात्मक अध्ययन करना है। लेखकद्वय ने शिक्षकों के शैक्षिक स्तर, उनके शिक्षण विधियों और छात्रों के दो समूहों पर किए गए परीक्षणों के माध्यम से सरकारी और निजी विद्यालयों में पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम की गुणवत्ता का आकलन किया है। लेखकद्वय ने पाया है कि सरकारी विद्यालयों में योग्य कर्मचारी, विशाल भवन और बुनियादी सुविधाएं हैं, निजी विद्यालयों की तुलना में स्थायी संकाय का अनुभव करते हैं।

रश्मिता एवं जैशमिन (2018) ने अपने शोध आलेख "चेन्नई में सार्वजनिक और निजी वित्त पोषित स्कूलों पर एक तुलनात्मक अध्ययन" में प्राथमिक और द्वितीयक दोनों डेटा का उपयोग कर माता–पिता की विशेषताओं की जाँच करने के लिए विश्लेषण किया है। उन्होंने पाया कि माता–पिता सार्वजनिक क्षेत्र के स्कूलों की तुलना में निजी क्षेत्र के स्कूलों को पसंद करते हैं। क्योंकि उनका मानना है कि सार्वजनिक क्षेत्र के स्कूलों में तुलनात्मक रूप से कम शैक्षणिक सुविधाएं और अनुपयुक्त शैक्षणिक माहौल है। साथ ही उनका मानना है कि सार्वजनिक स्कूलों में कुशल शिक्षकों की कमी है। इसलिए 90% माता–पिता संचार कौशल, करियर विकास और मानक बुनियादी ढांचे या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए निजी स्कूलों को चुन रहे हैं।

रावत एवं राजपूत (2017) ने अपने शोध आलेख "आगरा जिले के सरकारी और गैर–सरकारी स्कूलों के छात्रों के बीच सीखने की गुणवत्ता का तुलनात्मक अध्ययन" का उद्देश्य निजी और सरकारी विद्यालय के छात्रों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की तुलना करना था। अध्ययन में प्राथमिक और द्वितीयक दोनों डेटा का उपयोग कर पाया कि सीखने की गुणवत्ता के संबंध में सरकारी और निजी विद्यालय के छात्रों तथा उनकी सीखने की गुणवत्ता के मामले में महत्वपूर्ण अंतर है। निजी स्कूल सरकारी स्कूलों की तुलना में कहीं बेहतर मानक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बनाए रखते हैं। निजी स्कूलों के छात्रों के पास मार्गदर्शक और शिक्षित माता–पिता होते हैं। इसलिए छात्रो की शिक्षा गुणवत्तापूर्ण होती है और सरकारी स्कूलों से बेहतर होती है। शोध में यह भी पाया कि निजी स्कूल के छात्रों की सामाजिक और मौद्रिक स्थिति सरकारी स्कुल के छात्रों से बेहर स्थिति में होते हैं।

इसलिए छात्रों के सीखने की गुणवत्ता बेहतर होती है। छात्राएं गृह विज्ञान, कला विषय चुनती हैं और लड़के गणित चुनते हैं। साथ ही महिलाएं अपनी शिक्षा में पुरुषों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करती हैं। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है इसलिए सरकार को सभी विद्यालयों में सीखने के मानक लागू करने चाहिए।

रंजन (2014) ने अपने शोध आलेख "भारत में निजी विश्वविद्यालय और शिक्षा की गुणवत्ता" में कहा है कि देश में शैक्षणिक संस्थानों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ भारत में निजी उच्च शिक्षा अधिक प्रतिस्पर्धी हो रही है। भारत के केवल कुछ ही निजी स्कूलों/विश्वविद्यालयों ने कौशल विकास के लिए वांछित स्तर पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा और गुणवत्ता हासिल की है, लेकिन वे सभी समान स्तर की दक्षता के साथ कार्य कर रहे हैं।

तिवारी, अंजुम और खुराना (2013) ने अपने शोध आलेख "भारतीय उच्च शिक्षा में निजी क्षेत्र की भूमिका" में निजी उच्च शिक्षा संस्थानों में तेजी से वृद्धि पर प्रकाश डाला है। उन्होंने आलेख में कहा है कि निजी उच्च शिक्षा संस्थानों को परिणामों की गुणवत्ता के आधार पर विनियमित करने की आवश्यकता है। साथ ही सरकारी उच्च शिक्षा में सुधार की जरूरत है। वर्तमान में शिक्षा पर केंद्र सरकार की फंडिंग जीडीपी के 1% से भी कम है। अतः शिक्षा के लिए वर्तमान बजटीय आवंटन अपर्याप्त है जो निजी क्षेत्र के बजटीय आवंटन और आवश्यक आवंटन में अंतर को पाट सकता है।

धनकर (2010) अपने शोध आलेख ' शिक्षा में गुणवत्ता का विचार' में शिक्षा की गुणवत्ता की समस्या को स्वयं शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षा संस्थान और शिक्षातंत्र की गुणवत्ता में फर्क को चिह्नित करते हुए कागज–पेंसिल टेस्ट के जरिए शिक्षार्थी की उपलब्धि को जांचने के प्रयासों की संकीर्णता की आलोचना किया है और शिक्षा की गुणवत्ता को शिक्षार्थियों के लिए स्वतंत्र एवं अच्छे नैतिक जीवन के लिए आवश्यक योग्यताओं के विकास के रूप में देखता है।

किंगडम (1996) ने अपने शोध आलेख 'निजी और सार्वजनिक शिक्षा की गुणवत्ता और दक्षता' में शहरी भारत का एक केस अध्ययन। उन्होंने पाया कि सरकारी और निजी स्कूल अपनी लागत दक्षता में समान हैं लेकिन सार्वजनिक स्कूल निजी स्कूलों की तुलना में प्रतिकूल हैं। सरकारी वित्त पोषित स्कूलों की गुणवत्ता और लागत दक्षता में काफी सुधार करने की आवश्यकता है और निजी स्कूलों की दक्षता में वृद्धि होगी क्योंकि ये संस्थान तकनीकी रूप से अधिक कुशल और अधिक लागत कुशल हैं।

अध्ययन का उद्देश्य

अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

1. गैर–सरकारी और सरकारी स्कूल के छात्रों के बीच सीखने की गुणवत्ता की तुलना करना।
2. सरकारी विद्यालय के छात्र एवं छात्राओं की सीखने की गुणवत्ता की तुलना करना।
3. गैर–सरकारी विद्यालय के छात्र एवं छात्राओं की सीखने की गुणवत्ता की तुलना करना।

अध्ययन की परिकल्पना

1. सरकारी और गैर–सरकारी स्कूल के छात्रों में सीखने की गुणवत्ता में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है।
2. सरकारी स्कूलों के छात्र एवं छात्राओं की सीखने की गुणवत्ता में कोई खास अंतर नहीं है।
3. गैर–सरकारी विद्यालयों के छात्र एवं छात्राओं की सीखने की गुणवत्ता में कोई विशेष अंतर नहीं है।

कार्यप्रणाली

यह शोध भागलपुर जिला (बिहार) में आयोजित किया गया था। शोधकर्ता ने मुख्य रूप से भागलपुर शहर से सरल यादृच्छिक नमूनाकरण पद्धति का उपयोग कर नमूना का चयन किया। अध्ययन में स्वनिर्मित प्रश्नावली का उपयोग किया गया। अध्ययन के लिए केवल माध्यमिक विद्यालयों के 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों का चयन किया गया। नमूना आकार 100 विद्यार्थियों तक सीमित था। अध्ययन में 50 छात्र और 50 छात्राओं को शामिल किया गया। अध्ययन विभिन्न चरों को लेकर आयोजित किया गया था जो शिक्षा की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है। लेकिन अध्ययन के लिए केवल लिंग और स्कूल के प्रकार का चयन किया गया है। आंकड़ों के विश्लेषण के लिए टी–परीक्षण का उपयोग सांख्यिकीय तकनीक के रूप में किया गया था।

आंकड़ों का विश्लेषण और व्याख्या

तालिका 1 से 3 तक में सरकारी और गैर–सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की शिक्षा की गुणवत्ता का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए शोधकर्ता ने माध्य, मानक विचलन और टी–मान की गणना किया है।

तालिका 1: सरकारी और गैर–सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की शिक्षा की गुणवत्ता की तुलना

विद्यालय के प्रकार	आवृत्ति	माध्य	मानक विचलन	डीएफ	टी–मान	महत्व का स्तर
सरकारी विद्यालय	50	48.65	8.99	98	2.41	0.05 स्तर पर महत्वपूर्ण अंतर है
गैर–सरकारी विद्यालय	50	51.01	7.52			

स्रोतः प्राथमिक डेटा से परिकलित

तालिका 1 में दिखाया गया है कि गैर–सरकारी और सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों का शिक्षा की गुणवत्ता का औसत स्कोर क्रमशः 48.65 और 51.01 है, जिसमें मानक विचलन क्रमशः 8.99 और 7.52 है। उपरोक्त दो समूहों में 2.41 का टी–मान मिला, जो 0.05 के महत्व के स्तर पर महत्वपूर्ण है। यह सरकारी और गैर–सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शिक्षा की गुणवत्ता में अंतर को दिखाता है क्योंकि सरकारी विद्यालयों में शिक्षक सिर्फ लिपिकीय काम में व्यस्त रहते हैं और विद्यार्थियों के समग्र विकास पर अधिक ध्यान नहीं देते हैं। इस तरह, गैर–सरकारी और सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की पढ़ाई की गुणवत्ता में कोई महत्वपूर्ण अंतर है जो स्पष्ट रूप से बताता है कि गैर–सरकारी विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता सरकारी विद्यालयों से बेहतर है।

तालिका 2: सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों और छात्राओं की शिक्षा की गुणवत्ता की तुलना

चर	आवृत्ति	माध्य	मानक विचलन	डीएफ	टी–मान	महत्व का स्तर
छात्र	25	48.36	7.88	48	1.081	0.05 स्तर पर महत्वपूर्ण अंतर नहीं है
छात्रा	25	52.10	9.01			

स्रोतः प्राथमिक डेटा से परिकलित

तालिका 2 में पाया गया कि छात्रों का औसत मान 45.36 है, जबकि छात्राओं का औसत मान 52.10 है, जो एक बड़ा अंतर दर्शाता है। तालिका में दिखाया गया टी–मान है, जो महत्व के स्तर 0.05 से अधिक है। सरकारी विद्यालयों में छात्रों और छात्राओं की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए टी–मूल्य 3.081 प्राप्त हुआ, जो महत्व के स्तर 0.05 पर महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। इसलिए, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि छात्रों और छात्राओं को सरकारी विद्यालयों में समान प्रकार का वातावरण मिलता है जो उनके सीखने की क्षमता को बढ़ाता है। यही कारण है कि सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों की पढ़ाई की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण अंतर नहीं है।

तालिका 3: गैर–सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों और छात्राओं की शिक्षा की गुणवत्ता की तुलना

चर	आवृत्ति	माध्य	मानक विचलन	डीएफ	टी–मान	महत्व का स्तर
छात्र	25	49.36	6.73	48	1.661	0.05 स्तर पर महत्वपूर्ण अंतर नहीं है
छात्रा	25	52.50	7.94			

स्रोतः प्राथमिक डेटा से परिकलित

गैर–सरकारी विद्यालयों में छात्रों और छात्राओं की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए टी–मूल्य 1.661 प्राप्त हुआ, जो महत्व के स्तर 0.05 पर महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। इसलिए, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पुरुष और महिला विद्यार्थियों को गैर–सरकारी विद्यालयों में समान प्रकार का वातावरण मिलता है जो उनके सीखने की क्षमता को बढ़ाता है। यही कारण है कि गैर–सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों की पढ़ाई की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण अंतर नहीं है।

जाँच परिणाम

1. सीखने की गुणवत्ता के संबंध में सरकारी और गैर–सरकारी स्कूल के छात्रों के बीच महत्वपूर्ण अंतर पाया गया।
2. सरकारी स्कूल के छात्र एवं छात्राओं के बीच उनकी सीखने की गुणवत्ता के मामले में महत्वपूर्ण अंतर पाया गया।
3. गैर–सरकारी विद्यालय के छात्र एवं छात्राओं की सीखने की गुणवत्ता में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया गया।

चर्चा

उपरोक्त शोध परिणामों की पुष्टि रावत, बाबिता और राजपूत, अर्चना (2017), रक्ष्मिता और जैशमिन (2018).

रूबब व अन्य (2020), पापनास्तासिउ और ज़ेम्बिलास (2005) आदि ने भी किया है। शिक्षा की गुणवत्ता काफी हद तक शिक्षक की काम से संतुष्टि से संबंधित है जैसा कि पापनास्तासिउ और ज़ेम्बिलास (2005) ने भी कहा है। इस प्रकार, शिक्षक की नौकरी से संतुष्टि उसके शिक्षण चरित्र को प्रभावित करती है; इसके अलावा, शिक्षक को शिक्षण से क्या चाहता है और क्या

प्रस्ताव देता है, इसके बीच वास्तविक संबंध है जैसा कि गना (2011) ने भी पाया है। शोध के परिणामों से पता चलता है कि गैर–सरकारी विद्यालयों में शिक्षक अपने पसंदीदा विषयों को पढ़ाकर अधिक संतुष्ट हैं, जबकि सरकारी विद्यालयों में शिक्षक अपनी नौकरी और वेतन से अधिक संतुष्ट हैं। जैसा कि टूली व अन्य (2005) ने भी पाया कि नाइजीरिया में गैर–सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों की तुलना में सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों का वेतन तीन गुना अधिक है और स्नातक कम वेतन पर पढ़ना चाहते हैं ।

निष्कर्ष

उपरोक्त अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि सीखने की गुणवत्ता भी शिक्षण जितनी ही महत्वपूर्ण है। यह आवश्यक है कि सरकार शिक्षण के साथ–साथ सीखने में सुधार के लिए प्रभावी उपाय करे। यह देखा गया है कि गैर–सरकारी स्कूल सरकारी स्कूलों की तुलना में कहीं बेहतर मानक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बनाए रखते हैं। उनके पास धन के उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं है। गैर–सरकारी स्कूलों के पास अच्छी आधुनिक तकनीक और पाठ्यक्रम भी है। मुरलीधरन और सुंदररमन (2011) ने बताया कि अतिरिक्त स्कूली शिक्षा सामग्री प्रदान करने से छात्रों के प्रदर्शन में सुधार करने में मदद मिली, और सीखने की गुणवत्ता में सुधार के लिए अतिरिक्त अनुबंध शिक्षकों की आपूर्ति करना अधिक प्रभावी नीति थी। तो, यह कहा जा सकता है कि गैर–सरकारी स्कूल के छात्रों को सरकारी स्कूलों की तुलना में बेहतर शिक्षा मिलती है क्योंकि वे अधिक शिक्षकों की नियुक्ति करते हैं। गैर–सरकारी स्कूलों में छात्रों के माता–पिता शिक्षित और अमीर होते हैं, इसलिए छात्रों की शिक्षा में कोई अंतर नहीं होता है। दूसरी ओर सरकारी स्कूलों में छात्र अलग–अलग सामाजिक–आर्थिक स्थिति के होते हैं इसलिए उनके सीखने के मोर्चे पर अंतर होता है। इस अध्ययन के परिणाम बताते हैं कि सरकार को सीखने के अधिकतम स्तर पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और ऐसे कामकाजी तंत्र होने चाहिए जो इस मानक को सुनिश्चित करें। शिक्षकों को अन्य कार्य करने के बजाय छात्रों के लिए सीखने और सिखाने के स्तर को बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए क्योंकि सरकारी स्कूल उच्च शिक्षित शिक्षकों को नियुक्त करते हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है इसलिए सरकार को सभी स्कूलों में सीखने के मानक लागू करने चाहिए।

सन्दर्भ

किंगडम, जी.जी. (1996), ″निजी और सार्वजनिक शिक्षा की गुणवत्ता और दक्षताः शहरी भारत का एक केस अध्ययन″, पृ. 1–35

गना, ए.बी. (2011). एन असीसमेंट ऑफ टीचर्स जॉब सैटिस्फेक्शन एंड जॉब परफॉरमेंस इन थ्री सेलेक्टेड सेकेंडरी स्कूल्स ऑफ ब्रोनो स्टेट, नाईजीरिया, कॉन्टेन्टेल जे. एडुकेशन रिसर्च, वॉल्यूम 4(1), पृ. 24–28.

टूली, जे.; डिक्सन, पी. और ओलानियन, ओ. (2005), ″लागोस राज्य, नाइजीरिया के कम आय वाले क्षेत्रों में निजी और सार्वजनिक स्कूली शिक्षा, एक जनगणना और तुलनात्मक सर्वेक्षण″, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, वॉल्यूम 43, नंबर 3, पृ. 125–146.

तिवारी, आर.; अंजुम, बी. और खुराना, ए. (2013). ″भारतीय उच्च शिक्षा में निजी क्षेत्र की भूमिका″, गैलेक्सी इंटरनेशनल इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च जर्नल, वॉल्यूम 1(2), पृ. 75–83.

धनकर, रोहित (2010). शिक्षा में गुणवत्ता का विचार, शिक्षा–विमर्श, नवम्बर–दिसम्बर, 2010, पृ. 5–17.

पापनास्तासिउ, ई.सी. और ज़ेम्बिलास, एम. (2005). ″साइप्रस में सार्वजनिक और निजी किंडरगार्टन स्कूल शिक्षकों के बीच नौकरी की संतुष्टि″, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, वॉल्यूम 43, नंबर 3, पृ. 147–167.

बैरो, आर.जे. (2001). मानव पूंजी और विकास, एम. इकोन, रेव., 91(2), 12–17.

मुरलीधरन, के. एवं सुंदररमन, वी. (2011). शिक्षकों का प्रदर्शन वेतनः भारत से प्रायोगिक साक्ष्य, जे.पोलिट इकोन., 119 (1), 39–77.

रक्ष्मिता, के. और जैशमिन, के.एस. (2018). ″चेन्नई में सार्वजनिक और निजी वित्त पोषित स्कूलों पर एक तुलनात्मक अध्ययन″, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ प्योर एंड एप्लाइड मैथमैटिक्स (स्पेशल इश्यू), वॉल्यूम 120 नंबर 5, पृ. 245–254, ISSN:1314-3395 (online), http:// www.acadpubl.eu/hub/

रंजन, आर. (2014). ″भारत में निजी विश्वविद्यालय और शिक्षा की गुणवत्ता″, मानविकी सामाजिक विज्ञान और शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीय जर्नल (आईजेएचएसएसई) खंड 1, अंक 9, पृ. 140–144

रावत, बाबिता और राजपूत, अर्चना (2017). आगरा जिले के सरकारी और निजी विद्यालयों के छात्रों के बीच सीखने की गुणवत्ता का एक तुलनात्मक अध्ययन, भारतीय जर्नल ऑफ एप्लाइड रिसर्च, वॉल्यूम 7, अंक 5, मई 2017, पृ. 564–566, ISSN - 2249-555X.

रूबब, राणा और अवन, अब्दुल गफूर (2020). सरकारी और निजी माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता का एक तुलनात्मक अध्ययनः पाकिस्तान के खानवाल और वाइरी जिलों का केस स्टडी, ग्लोबल जर्नल ऑफ मैनेजमेंट, सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज, 537 वॉल्यूम 6(3) जुलाई–सितंबर, 2020, पृ. 537–558, www.gjmsweb.com.

हनुशेक, ई.ए. एवं किम्को (2000). स्कूली शिक्षा, श्रम–शक्ति की गुणवत्ता, और राष्ट्रों का विकास एम, इकोन, रेव.90 (5), 1184–1208।

हेन्स (1993). स्नातक सामाजिक कार्य छात्रों के बीच मूल्य एकीकरण पिरामिड मॉड्यूल की प्रभावशीलता की एक परीक्षा, अप्रकाशित डॉक्टरेट शोध प्रबंध. फ्लोरिडा राज्य विश्वविद्यालय।